श्रीमन्, 1972 में एक बार बुनकरों ने स्टेपल धागा और सूत की महंगाई को लेकर आन्दोलन किया था और उस समय केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों ने यह तय किया था कि 22 ऐसी कताई मिलें खोली जायेंगी राज्य सरकार और सहकारी संस्थाओं के द्वारा जिनके माध्यम से बुनकरों को सूत सस्ती दर पर दिया जाएगा । लेकिन श्रीमन्, केवल 12 कताई मिलें खोली गई हैं और जो 12 कताई मिलें खोली गई हैं वह भी उनको सूत महंगा दे रही हैं जिसका नतीजा यह हो रहा है कि उन मिलों को खोलने का जो उद्देश्य था वह बुनकरों को सस्ती दर पर सूत दिया जाएगा, उनको वह न देकर वह सूत मिलों तथा बड़े-बड़े सूत व्यापारियों को दिया जा रहा है जिसका परिणाम बुनकर भुगत रहे हैं ।

श्रीमन्, चार कताई मिलें इस प्रकार की खोली गई जो बुनकरों की सहकारी संस्थाओं की हैं, किन्तु वे भी बुनकरों का शोषण कर रही हैं । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बस्ती जिले में मगहर की सहकारी कताई मिल है जिस के द्वारा बुनकरों की दुर्दशा की जा रही है । बुनकरों को सीधे सूत उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और वह भ्रष्टाचार का अड्डा बन रही हैं । जनता सरकार ने धोती-साड़ी उत्पादन योजना बनाई किन्तु जितना वहां उत्पादन हो रहा है उसमें जबरदस्त भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है और बुनकरों के शोषण को छोड़कर और कुछ नहीं हो रहा है । उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है ।

श्रीमन्, प्रधान मंत्री जी से पीछे एक प्रतिनिधिमंडल मिला था । यह प्रतिनिधिमंडल केन्द्रीय उद्योग मंत्री और श्रम मंत्री से भी मिला और उनको अपनी समस्याओं से अवगत कराया । मैं कहना चाहता हूं कि बुनकरों की वास्तविक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जो धोती-साड़ी उत्पादन की योजना है उसमें आमूलचूल परिवर्तन किया जाए और साथ ही साथ बुनकरों के प्रत्येक उत्पादन केन्द्र पर उनके माल की नकद खरीदारी का नियम अनिवार्य रूप से लागू किया जाए तो शायद इस व्यवस्था से कुछ उनको राहत मिल सकेगी ।

REFERENCE TO THE REPORTED FAST UNDERTAKEN BY SOME STATION MASTERS OUTSIDE THE RAILWAY MINISTER'S RESIDENCE TO PRESS THEIR DEMANDS

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, through you I want to draw the attention of the Government to a matter of urgent public importance. The matter is that several Station Masters have been observing a hunger strike in front of the residence of the Railway Minister at Delhi since 21st April, 1983 to press for the settlement of some of their long-standing demands. And what is the most disquieting feature to note is that two of the fasting Station Masters had to be shifted to hospital but they have still been continuing their fast in the hospital itself because the Railway Minister has not yet asked any of the representatives of the All-India Station Masters' Association for a negotiated settlement.

Sir, the most important part of the thing is that the demands for the settlement of which the Station Masters have been observing fast even in the hospital are very small demands, and it involves very little finance for settling those demands. And two of these demands have already been accepted by the Railway Board in 1982, but they have not implemented them as yet. And this is not the first time

[Shri Dipen Ghosh]

that they have sought to draw the attention of the Railway Minister to these demands. Since 1980 they have been pressing for these demands and they have been undertaking certain forms of agitations starting from signature campaign to demonstration. But having failed to draw the attention of the Railway Minister, they have started this indifinite fast. And if the Railway Minister is not told by you, Sir, to intervene and to have a negotiated settlement, then these Station Masters may have to go in for a higher form of agitation which may result in the dislocation of the entire Railway system.

So Sir, I draw your attention and, through you, I want to draw the attention of the Government to this particular matter. And these issues are very simple like restructuring of the cadre, some uniform allowance, etc. All these things involve very little finances. So I would appeal to you to ask the Railway Minister to immediately arrive at a negotiated settlement.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE (West Bengal): Sir, this is a matter not of Special Mention, Half-an-Hour Discussion should be allowed on this.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : दीपेन घोष जी ने जो बात कही है मैं उसका समर्थन करता हूं । आडवाणी साहब खुद धरना देने वाले मेम्बरों के पास गये । 6-7 दिन से वे भूख हड़ताल पर हैं । उनकी हालत खराब है और जो रेल मंत्री हैं वे बाहर हैं और आज शाम को चार बजे आने वाले हैं । मेरा आपके माध्यम से उनसे निवेदन है कि वे वहां से आने के बाद घर में घुसने से पहले हड़तालियों से मिलें और वे डिमांड्स जो उन्होंने 25-1-82 को, 23-5-82 को स्वीकार कर ली हैं उनके बारे में आश्वासन दें कि हम उनको पूरा करेंगे । अन्यथा उनकी हालत और खराब होती चली जायेगी । यह किसी दल विशेष का सवाल नहीं है । जितने भी सदन के सदस्य हैं चाहे उधर बैठे हों वे भी इस बात को स्वीकार करेंगे । मेरा आपसे निवेदन है कि मंत्री महोदय से कहें कि चार बजे जो वह तशरीफ ला रहे हैं वह घर में घुसने से पहले उनसे जाकर मिलें और आज ही उनकी हड़ताल तोड़ने की व्यवस्था करें ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (मध्य प्रदेश) : मिनिस्टर आफ स्टेट यहां हैं । यह तो सिर्फ इम्पलीमेंट करने का सवाल है ।

SHRI DIPEN GHOSH: The Minister is entering the house and going out of the house but he is not calling the representatives.

श्री उपसभापति : इतनी छोटी-सी बात पर वे भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं । यह तो बातचीत से भी हल किया जा सकता है ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मिनिस्टर आफ स्टेट यहां हैं वे उनके पास जा सकते हैं ।

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we start the discussion on the working of the Ministry of Home Affairs—Shri Era Sezhiyan.

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । मैं यह किताब लेकर खड़ा हुआ हूं इसलिये कि आप पूछेंगे किस प्वाइंट से आप बोल रहे हैं । यह किताब है